आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 04.02.2026 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया।
- पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में देहरादून में अपराध और कानून व्यवस्था पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।
- विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2 हजार 364 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू।
- कीवी नीति के तहत पिथौरागढ़ जिले को कीवी क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ट्राउट प्रोत्साहन योजना

प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन के क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल करेंसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल वित्तीय समावेशन और डिजिटल उत्तराखंड के सरकार के संकल्प को और मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालकों को सशक्त बनाने और राज्य की आर्थिकी को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं।

पुलिस महानिदेशक बैठक

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में देहरादून में अपराध और कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था की स्थिति, विवेचनाओं और जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर जरूरी दिशा–निर्देश दिए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लैंड फ्रॉड मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई करने के साथ ही सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सतर्कता विभाग को पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गढ़वाल और कुमाऊँ रेंज प्रभारी सहित सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा ई–रिक्शा चालकों के लिए चलाये जा रहे सत्यापन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने ई–रिक्शा चालकों को सत्यापन अभियान के मकसद से रूबरू कराया और यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित संचालन व यात्रियों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि बिना सत्यापन के किसी भी ई–रिक्शा का संचालन ना किया जाए। निरिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सत्यापित ई–रिक्शाओं पर रूट–वाइज रंग–कोडित क्यूआर स्टिकर चस्पा किए। यह क्यूआर स्टिकर पुलिस चालक या मालिक के सत्यापन और आरआई द्वारा वाहन सत्यापन के बाद ही जारी किए जा रहे हैं।

परीक्षा पे चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आगामी शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जा पूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यवहारिक तरीके अपनाने, सामन्जस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों के साथ देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और उनके अधिकारिक आवास, सात लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली में महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए।

भर्ती

विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2 हजार 364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की आधिकारिक बेवसाइट के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि पांच मार्च निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती आउटससोर्स के माध्यम से की जायेगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्मिकों को प्रत्येक माह 15 हजार रूपये मानदेय दिया जायेगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भर्ती के लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।

कीवी पिथौरागढ़

प्रदेश में कीवी नीति के तहत पिथौरागढ़ जिले को कीवी क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मौजूदा समय में जिले की एक हजार 560 नाली से अधिक भूमि पर कीवी की व्यावसायिक खेती की जा रही है। मुख्य उद्यान अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया पिथौरागढ़ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां कीवी उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। इसे देखते हुए विभाग द्वारा किसानों को पौध के साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कीवी की खेती को एक स्थायी आजीविका का साधन बनाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित व संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने चामासारी और सरोना सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को तीन दिन के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पुश्ता निर्माण सहित अन्य कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दिलाकर कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके। श्री जोशी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया।

फास्टफूड प्रशिक्षण

भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग में 12 दिवसीय निःशुल्क फास्ट फूड प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें फास्ट फूड उद्योग में कुशल बनाना है। प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड उत्पाद तैयार करने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। प्रशिक्षण ले रहे शुभम सेमवाल और संजय ने कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल उनके कौशल का विकास करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भविष्य में बैंक से मिलने वाली सहायता, ऋण सुविधाएं और वित्तीय सलाह के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में चमोली जिले के देवाल विकासखंड के ग्राम ल्वाणी के मत्स्य पालन उद्यमी मोहन सिंह बिष्ट ने मुलाकात की। श्री बिष्ट वर्ष 2017 से ट्राउट मछली पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि उनके द्वारा उत्पादित मछली आईटीबीपी और एसएसबी को आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने अपने गांव में एकीकृत कृषि शुरू करने के लिए सहयोग का अनुरोध भी किया। राज्यपाल ने श्री बिष्ट के प्रयासों को उत्तराखण्ड के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नवाचारी सोच और उद्यमशीलता ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।